www.jagran.com राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
रविवार 3 फरवरी 2019

दैनिक जागरण

अंतहीन इच्छाओं से केवल संतुष्टि का भाव ही बचा सकता है

एचएएल की नाकामी

बेंगलुरु के पास लड़ाकू विमान मिराज-2000 का दुर्घटनाग्रस्त होना और उसमें वायु सेना के दो अनुभवी पायलटों की मौत हो जाना एक बेहद गंभीर घटना है। आवश्यक केवल यह नहीं है कि इस घटना पर गंभीरता का परिचय दिया जाए, बल्कि यह भी है कि उन कारणों की तह तक सचमुच जाया जाए जिनके चलते देश ने एक लड़ाकू विमान के साथ अपने दो पायलट भी खो दिए। एक साथ दो पायलटों की मौत इसलिए बड़ा नुकसान है, क्योंकि लडाकू विमानों के पायलट बेहद गहन प्रशिक्षण के बाद तैयार होते हैं। चूंकि उनके प्रशिक्षण में समय के साथ तमाम संसाधन भी लगते हैं इसलिए परीक्षण उड़ान के दौरान उनकी मौत राष्ट्रीय क्षति है। निःसंदेह लडाकू विमानों के साथ कुछ न कुछ जोखिम रहता है, लेकिन आम तौर पर परीक्षण उड़ानों के दौरान कोई गड़बड़ी होने पर पायलट खुद को बचा लेते हैं। बेंगलुरु में ऐसा नहीं हो सका। यहां मिराज-2000 लड़ाकू विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद यदि उसे उन्नत करने वाली हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी एचएएल रक्षा विशेषज्ञों और पूर्व सैन्य अधिकारियों के साथ आम लोगों के निशाने पर आ गई है तो यह स्वाभाविक है। अगर यह माना जा रहा है कि एचएएल की खामी परीक्षण उड़ान पर निकले पायलटों पर गाज बनकर गिरी तो इसके लिए यह सरकारी कंपनी अपने अलावा अन्य किसी को दोष नहीं दे सकती। लड़ाकू विमानों की मरम्मत करने और उन्हें उन्नत बनाने में एचएएल का रिकार्ड बहुत ही खराब है। यह वही एचएएल है जिसकी तथाकथित उपेक्षा का रोना कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी रोते रहते हैं। क्या राफेल सौदे को विवादास्पद बताने की धुन में एचएएल की कामयाबी और महानता के गुण गा रहे राहुल गांधी मिराज के दुर्घटनाग्रस्त होने पर कुछ बोलेंगे? क्या उन्हें यह अहसास हो पा रहा है कि वह अपने संकीर्ण राजनीतिक फायदे के लिए जिस एचएएल को एक मोहरा बना रहे हैं उसका कामकाज बेहद दयनीय है?

संकीर्ण राजनीतिक हितों के फेर में एचएएल की नाकामियों की अनदेखी करना राष्ट्रीय हितों को जानबूझकर चोट पहुंचाने के अलावा और कुछ नहीं। इससे संतुष्ट नहीं हुआ जा सकता कि मिराज हादसे में दो पायलटों के मारे जाने की घटना की जांच के आदेश दे दिए गए हैं, क्योंकि इस तरह की तमाम जांच पहले भी हो चुकी हैं और नतीजा शून्य है। इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि चंद दिन पहले उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में जो जगुआर विमान नष्ट हुआ था वह भी एचएएल ने उन्नत किया था। एचएएल की ओर से तैयार अथवा उन्नत किए गए विमान जिस तरह हादसे का शिकार होते रहते हैं उसे देखते हुए किसी को इस सवाल का जवाब देना ही होगा कि आखिर इस सरकारी कंपनी के दोयम दर्जे के कामकाज की अनदेखी कब तक की जाती रहेगी? यह अपेक्षाओं पर खरा न उतर पाने वाली सरकारी कंपनियों के बेजा बचाव की प्रवृत्ति का ही परिणाम है कि रक्षा सामग्री के उत्पादन के मामले में भारत का प्रदर्शन बहुत ही गया-बीता है। अब जब रक्षा विशेषज्ञों के साथ वायु सेना प्रमुख भी एचएएल के कामकाज से संतुष्ट नहीं तब फिर यह जरूरी है कि हमारे नीति-नियंता चेत जाएं।

विपक्ष का विरोध

पश्चिम बंगाल विधानसभा में शुक्रवार को बजट सत्र के शुभारंभ पर राज्यपाल केसरीनाथ त्रिपाठी जब अभिभाषण पढ़ रहे थे तो कांग्रेस और वाममोर्चा के सदस्यों ने शोर मचाना शुरू कर दिया। वे पोस्टर-बैनर लगाकर सदन में पहुंचे थे, जिन पर सरकार विरोधी नारे लिखे थे। अभिभाषण के दौरान वे अपनी सीट पर खड़े हो गए और फिर शोर मचाते हुए वेल में उतर आए। अभिभाषण खत्म होने तक उन्होंने सदन में शोर मचाया और सरकार विरोधी नारे लगाए। बाद में जब धन्यवाद प्रस्ताव हुआ तो विपक्ष के नेता अब्दुल मन्नान ने अभिभाषण पर बहस नहीं कराने के सरकार के निर्णय पर सवाल उठाया। इस पर स्पीकर विमान बनर्जी और संसदीय कार्य मंत्री पार्थ चटर्जी के साथ मन्नान की नोकझोंक हुई। स्पीकर ने मन्नान को आश्वस्त किया कि अगले सत्र में राज्यपाल के अभिभाषण पर बहस कराई जाएगी। खैर, स्पीकर के हस्तक्षेप से विपक्षी सदस्य शांत हो गए। विपक्ष ने स्पष्ट किया है कि उनका विरोध जारी रहेगा, जो सदन की कार्यवाही के बहिष्कार की हद तक जा सकता है। स्पीकर ने अभिभाषण पर चार दिनों तक सदन में बहस कराने की विपक्ष की मांग को स्वीकार नहीं किया है। विपक्ष के नेता अब्दुल मन्नान का कहना है कि अभिभाषण पर लगातार बहस कराने की परंपरा है। सोमवार को वित्त मंत्री बजट पेश करेंगे और मंगलवार को ही बजट सत्र संपन्न हो जाएगा। शुक्रवार को राज्यपाल के अभिभाषण से बजट सत्र शुरू हुआ और मंगलवार यानी तीन दिनों में ही बजट सत्र का समापन कर दिया जाएगा। विधानसभा के संसदीय इतिहास में इतना संक्षिप्त बजट सत्र कभी नहीं हुआ है। इस पर संसदीय कार्यमंत्री पार्थ चटर्जी का कहना है कि विधानसभा की नियमावली में कहीं नहीं लिखा है कि राज्यपाल के अभिभाषण पर बाद में बहस नहीं कराई जा सकती है। उनका यह तर्क सही हो सकता है, लेकिन विपक्ष के विरोध का भी औचित्य है। आखिर जब विधायी कार्य का अभाव है तो कम से कम राज्यपाल के अभिभाषण और बजट पर पर्याप्त बहस कराने की व्यवस्था करने की विपक्ष की मांग को अनुचित नहीं कहा जा सकता है। विपक्ष सर्वदलीय और विधानसभा की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक का बहिष्कार कर चुका है।

चुनाव के साथ आर्थिक सेहत की चिंता

संजय गुप्त

यह संतोषजनक है कि सरकार ने उन्हें गलत साबित किया जो यह मान रहे थे तीन राज्यों के चुनाव में मिले झटके के बाद वह लोक-लुभावन योजनाओं की झड़ी लगा देगी

मोदी सरकार ने अपने आखिरी बजट में गरीब किसानों, मजदूरों और मध्यम वर्ग को राहत देने वाली जो अनेक घोषणाएं कीं उनके बारे में संदेह नहीं कि वे आम चुनाव को ध्यान में रखकर ही की गई हैं। चुनावी वर्ष में प्रवेश कर रही किसी भी सरकार के लिए मतदाताओं को रिझाने के लिए घोषणाएं करना उसकी अपनी राजनीतिक जरूरत होती है। इस जरूरत की पूर्ति करना उसका अधिकार है। हर सत्तारूढ़ राजनीतिक दल चुनाव के पहले बजट में जनता को लुभाने की कोशिश इसलिए भी करता है, क्योंकि पहले की घोषणाओं का असर एक बड़ी हद तक कम या खत्म हो जाता है अथवा वे उतनी आकर्षक नहीं रह जातीं। इस बार मोदी सरकार ने जो घोषणाएं की हैं उनमें सबसे महत्वपूर्ण है छोटे किसानों को सीधे उनके खाते में सालाना छह हजार रुपये देना। यह योजना इसलिए विशेष है, क्योंकि अन्य कल्याणकारी योजनाओं में अफसरशाही की निर्णायक भूमिका होने के कारण लाभार्थियों को समुचित लाभ नहीं मिल पाता था या फिर वे भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाती थीं। इस बारे में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी का यह कहना सही ही था कि केंद्र सरकार किसी योजना में एक रुपया भेजती है तो लाभार्थी तक पहुंचते-पहुंचते 10-15 पैसे ही रह जाते हैं। ऐसा इसलिए होता था, क्योंकि पहले की योजनाएं सीधे लाभार्थी के खाते में धन देने यानी डीबीटी पर आधारित नहीं होती थीं। डिजिटल तकनीक के चलते अब ऐसा करना आसान हो गया है और अनेक योजनाओं में इसका सफल परीक्षण भी हो चुका है। एक तथ्य यह भी है कि तब बहुत कम गरीबों के पास अपने बैंक खाते होते थे। अब करीब-करीब सभी गरीबों के पास जन-धन खाता है। यदि पहले के सिस्टम के रहते छोटे किसानों को छह हजार रुपये सालाना की सहायता देने की कोई योजना शुरू की जाती तो अच्छी-खासी रकम सिस्टम में ही खप जाती और फिर भी सभी लाभार्थियों को रियायत देना मुश्किल होता।

अंतरिम बजट में मोदी सरकार की एक अन्य उल्लेखनीय घोषणा पशुपालक किसानों को कर्ज में दो प्रतिशत की छूट देने की है। मनरेगा के लिए 60,000 करोड़ का आवंटन भी ग्रामीण जनता को राहत देने वाला है। असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को तीन हजार रुपये की मासिक पेंशन देने की घोषणा ने भी सबका ध्यान खींचा है। सामाजिक सुरक्षा को सुनिश्चित करने वाली इस घोषणा के अलावा मोदी सरकार ने आंगनबाड़ी और आशा योजना के तहत मानदेय में 50 प्रतिशत वृद्धि तो की ही है, कामकाजी महिलाओं का मातृत्व अवकाश 26 हफ्ते किया है। महिलाओं को लाभ देने वाली एक अन्य घोषणा उज्ज्वला योजना के तहत दो करोड़ मुफ्त गैस कनेक्शन देने की भी है। अंतरिम बजट की एक और बड़ी घोषणा पांच लाख रुपये तक की आय को आयकर से मुक्त करने की है। सामान्य बचत योजनाओं में निवेश करने पर आयकर में छूट का यह लाभ 6.5 लाख रुपये तक बढ़ जाएगा। स्टैंडर्ड डिडक्शन की सीमा को 40 हजार रुपये से बढ़ाकर 50 हजार रुपये करने से भी मध्य वर्ग को लाभ मिलेगा।

अवधेश राजपूत

इस वर्ग के लिए एक आकर्षण यह भी है कि अब दूसरे घर से मिलने वाले अनुमानित किराये पर टैक्स नहीं देना होगा। इसी तरह एफडी के ब्याज पर 40 हजार रुपये तक टैक्स नहीं लगेगा। लोगों को सीधे राहत पहुंचाने वाली इन घोषणाओं के अतिरिक्त सरकार ने कुछ ऐसी घोषणाएं भी की हैं जिनसे आम आदमी को कुछ न कुछ परोक्ष लाभ मिलेगा। सरकार ने जो कल्याणकारी घोषणाएं की हैं उनसे करीब 25 करोड़ लोगों के लाभान्वित होने का अनुमान है। इनमें 10-12 करोड़ छोटे एवं सीमांत किसानों के अलावा असंगठित क्षेत्र के दस करोड़ श्रमिक हैं। इसके अलावा तीन करोड़ आयकर दाता भी हैं, जो टैक्स छूट से लाभान्वित हुए हैं। माना जा रहा है कि अगर इनमें से आधे लोगों ने भी भाजपा के पक्ष में मतदान किया तो वह आसानी से फिर सरकार बनाने में कामयाब हो सकती है।

बजट घोषणाओं के बाद स्वाभाविक तौर पर जहां भाजपा और सरकार यह मान रही है कि वह किसानों, मजदूरों के साथ मध्य वर्ग को संतुष्ट करने में सफल रहेगी वहीं विपक्ष इन घोषणाओं को नाकाफी और नाकाम बताने में जुट गया है। छोटे किसानों को साल में छह हजार रुपये की मदद देने के फैसले का कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने यह कहते हुए उपहास उड़ाया कि यह राशि तो 17 रुपये प्रतिदिन ही बैठती है।

कांग्रेस ने अपने नेतृत्व वाली संप्रग-एक सरकार के अंतिम दिनों में किसानों का 70 हजार करोड़ रुपये का कर्ज माफ किया था और इसके सहारे चुनाव जीतने में कामयाबी हासिल की थी। क्या उस कर्ज माफी से किसानों और देश का कोई भला हुआ था? तथ्य तो यही है कि संप्रग-2 सरकार के समय भी किसानों की हालत खराब रही। बीते कुछ समय से एक सोचा-समझा अभियान यह जताने के लिए चलाया जा रहा है कि किसानों की हालत बहुत खराब है और इसके लिए मोदी सरकार ही पूरी तौर पर जिम्मेदार है। यह ठीक है कि पिछले वर्षों में इस सरकार ने किसानों के लिए जो कुछ किया उससे उनकी स्थिति में वैसा सुधार नहीं आ सका जैसा आना चाहिए था, लेकिन इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती है कि मोदी सरकार की ओर से जो कदम उठाए गए हैं वे दीर्घकालिक सुधारों पर केंद्रित हैं।

निःसंदेह यह समय ही बताएगा कि आगामी आम चुनाव में मतदाता किसे वोट देते हैं और किसकी सरकार बनेगी, लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि मोदी सरकार के पास अंतरिम बजट के पहले भी किसानों और मजदूरों को राहत देने वाली योजनाओं को शुरू करने का अवसर था। पता नहीं इस अवसर का लाभ क्यों नहीं उठाया गया? यदि ये योजनाएं पहले ही शुरू की जातीं तो शायद आज स्थिति दूसरी होती। ध्यान रहे कि यदि गरीबों को कल्याणकारी योजनाओं के तहत सीधे पैसा मिले तो वे उसे अपने तरीके से और अपनी जरूरत के हिसाब से खर्च करने में समर्थ होते हैं। इसी कारण यह कहा जाता है कि अन्य मदों में सब्सिडी को समाप्त कर लाभार्थियों को सीधे धनराशि उपलब्ध कराई जाए। इससे उनके जीवन स्तर में कहीं बेहतर तरीके से सुधार आ सकता है। देखना है कि किसानों को सीधे पैसा देने की योजना कितनी लाभदायक साबित होती है? जो भी हो, यह गौर करने लायक है कि सरकार ने वित्तीय अनुशासन के चलते पैसा पानी की तरह बहाने से परहेज किया।

इसके विपरीत पहले की सरकारों ने चुनावी लाभ के लिए वित्तीय अनुशासन की अनदेखी कर राजकोषीय घाटे को बढ़ने दिया। मोदी सरकार ने वित्तीय अनुशासन का परिचय देकर परिपक्वता का ही प्रदर्शन किया है। यह भी उल्लेखनीय है कि पार्टी और सरकार ने यह भी साबित करने की कोशिश की है कि उसे अपने पर भरोसा है। यह संतोषजनक है कि उसने उन लोगों को गलत साबित किया जो यह मान रहे थे तीन राज्यों के चुनावों में मिले झटके के बाद सरकार मजबूरी में लोक-लुभावन योजनाओं की झड़ी लगा देगी। यह अच्छा हुआ कि भाजपा और मोदी सरकार ने इन लोगों की ओर से बनाए जा रहे दबाव में आने से इन्कार किया।

response@jagran.com

साहित्य में साहस का प्रदर्शन

साकेत सूर्येश

विरले ही ऐसा कोई अवसर उत्पन्न होता है जब आपका लिखा हुआ कुछ नजर में आकर पढ़ लिया जाता है

मेरा मानना है कि भयभीत लोगों का साहस और बेमौका बोल पड़ने का शौक साहित्य, विशेषकर व्यंग्य को जन्म देता है। आत्मा के भीतर की कुलबुलाहट जब मध्यमवर्गीय भीरूता के संपर्क में आती है तो व्यक्ति व्यंग्य लिखने लगता है। इसका आनंद यह होता है कि लेखक मन ही मन अपने पराक्रम पर मुग्ध हो लेता है और किसी को पता भी नहीं चलता कि तीर चला किधर और लगा कहां?

हिंदी के व्यंग्य लेखक प्रायः अधिक साहसी होते हैं। इधर कुछ समय से अंग्रेजी लेखक भी साहसी होने का दावा पेश करते रहे हैं। प्रेमचंद के फटे जूतों पर दावा ठोकते हुए वे प्रतिष्ठित और साधन-संपन्न साहित्य सम्मेलनों के मंच से सरकार को कोसते हैं और मजरूह की मासूमियत ओढ़कर तंत्र के दमन की शिकायत करते हुए फर्राटे से अपनी फेरारी मे निकल जाते हैं। जब ये सरकार को कोसते हैं तो उनका साहस देखकर किसी भी नए लेखक का अचंभित होना और पथभ्रमित हो जाना संभव है, किंतु निकट से विश्लेषण पर हम पाते हैं कि ये सरकार का विरोध करते हैं, सत्ता का नहीं। वर्तमान में सत्ता और सरकार का अर्थ भिन्न है।

इस सारी गोल-मोल कथा का अभिप्राय यह है कि अंग्रेजी लेखक, जो अक्सर पत्रकार भी होता है, जो मंत्रिमंडल नियुक्तियों का अधिकार खोकर पुनः सत्ता और सरकार के एकीकरण को प्रयासरत रहता है, भले ही छद्म शौर्य पर तालियां जमा कर ले, महिमामंडित हो ले, साहस का फुल कोटा और अधिकार केवल और केवल हिंदी व्यंग्य लेखन को ही प्राप्त है। अंग्रेजी में एक शब्द है 'ब्रिंकमैनशिप' जिसका हिंदी अनुवाद-कुल्हाड़ी पर पैर मारने-की प्रवृत्ति माना जा सकता है। जब हम 70 के दशक में आपातकाल के आसपास शरद जोशी जैसे लेखकों को इंदिरा जी पर, भजनलाल जी पर लिखते देखते हैं तो पाते हैं कि यह प्रवृत्ति हिंदी व्यंग्यकारों में प्रचुर मात्रा में भरी है। मुझे लगता है मेरा भी ऐसा स्वभाव है। इससे पहले आप मेरे इस प्रकार गाल बजाने से उत्साहित हो उठें, मैं अपने संदर्भ में इस प्रवृत्ति की तह में जाता हूं। वैसे तह तक जाने से मैं और आप बहुत ज्ञानी नहीं हो जाएंगे, किंतु फिर भी मैं जाऊंगा और मेरा निवेदन है कि आप भी आएं, क्योंकि मुझे तो अपनी बात हर हाल में कहनी ही है और चूंकि आप इन पंक्तियों को पढ़ रहे हैं इसलिए मुझे यह भी पता है कि आपके पास समय है। सो तह तक जाने से मुझे लगता है कि हिंदी व्यंग्यकार के तौर पर अपने साहस के पीछे मेरा अपठनीय होना है और उपेक्षित होना है।

बहुधा तीक्ष्ण से तीक्ष्ण लेखन संपादकों की सजग दृष्टि के पार इसी विश्वास के कारण हो जाता है कि इसे पढ़ता कौन है? इस व्यंग्य वीरता के पीछे भारतीय समाज का कान्वेंटीकरण है। हिंदी व्यंग्यकार अपनी साहित्यिक नगण्यता को लेकर आश्वस्त होता है अतः 'अपन किसी के बाप से नहीं डरते' का भाव लिखकर लेखनी उठाता है और वाम-दक्षिण का भेद त्यागकर उत्पात मचाता है। वह यह नहीं बताता कि इस वीरता के पीछे अपन को किसी का बाप भी नहीं पढ़ता-वाला विश्वास भी है। विरले ही ऐसा कोई अवसर उत्पन्न होता है जब आपका लिखा हुआ कुछ पढ़ लिया जाता है और आपसे कहा जाता है कि थोड़ा नरम कर दें, बदल दें। ऐसे समय हिंदी व्यंग्यकार उस मध्यवर्गीय बालक की भांति चमत्कृत सा हो जाता है जिसके अभिभावक उसे चलना-बोलना तो बड़ी शिद्दत से सिखाते हैं और फिर मौके की नजाकत के मुताबिक चुपचाप बैठ जाने को कह देते हैं। ऐसा मेरे साथ बहुत कम ही होता है। मेरे प्रकाशकों का भी मानना है कि इसके हाशिये पर हीरो बनने से किसी का कुछ बिगड़ना नही है।

मेरा मानना है कि जैसा बौद्धिक कान्वेंटीकरण प्रबुद्ध, प्रतिष्ठित भारतीय समाज में आज है, हिंदी व्यंग्यकार सुरक्षित भाव से व्यंग्य लिखे जा सकता है। साहित्यिक पुरस्कारों के अभाव में आप उन्हें लौटाकर समाज की दिशा और दशा तो बदल नहीं सकते हैं, सो बेखटके लिखें, आग उगलें और साहित्य के न सही रद्दी-कबाड़ी वालों के प्रिय लेखक बनने का प्रयास करें। यही मैं कर रहा हूं। मैं निरंतर लिखते रहकर रद्दीवालों के माध्यम से गृहिणियों को स्टील की कटोरियां दिलाने को कटिबद्ध हूं। मुझे विश्वास सा हो चला है कि कबाड़ी समाज रद्दी के निर्माण में बहुमूल्य योगदान के लिए एक न एक दिन मुझे महान साहित्यकार मानेगा। मेरी अपठित लेखक होने की छद्म वीरता एक दिन मुझे साहसी और जुझारू लेखक का सम्मान अवश्य देगी, ऐसा मुझे विश्वास है। मुझे पदक और कप न मिलें, जिन्हें मैं जरूरत के वक्त लौटा सकूं, परंतु मैं अपने पाठकों को प्लेट और कटोरियां अवश्य दिलाऊंगा, ऐसा मेरा प्रयास है।

response@jagran.com

तथ्य-कथ्य | स्वचालित कारों पर घटता भरोसा

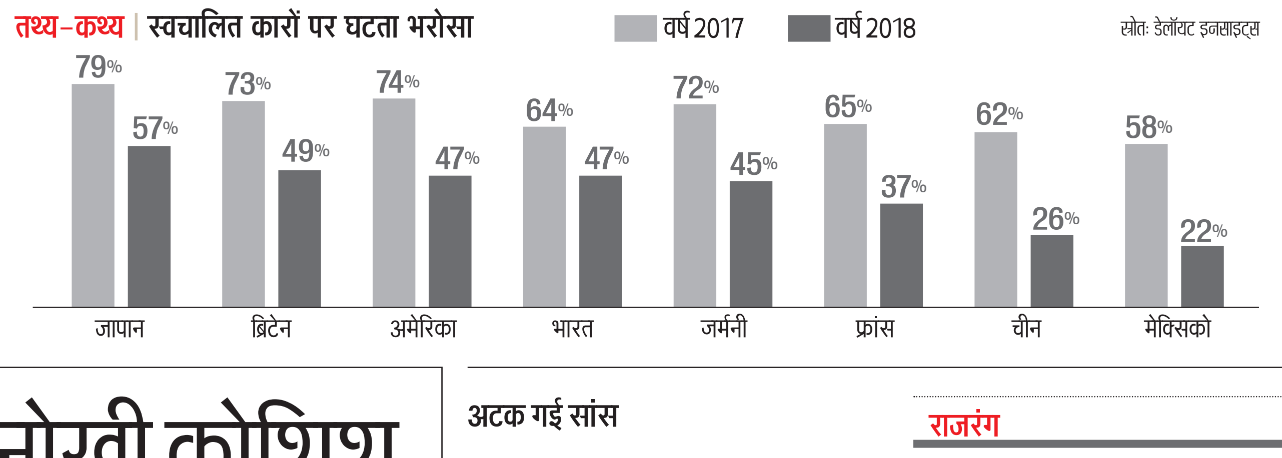

ऊर्जा

तीर्थ

हमारी संस्कृति में तीर्थों के महत्व का विस्तार से वर्णन है। उन्हें धर्म, संस्कृति और जीवनशैली से जोड़कर देखा जाता है। संस्कृत में तीर्थ का अर्थ है-पार उतारने वाला, पाप से तारने वाला, पवित्र भावों का संचार करने में समर्थ आदि। तीर्थों की महिमा को हमारे मनीषियों ने कुछ इस प्रकार समझाया है कि तीर्थों में सकारात्मक ऊर्जा व्याप्त रहती है, जो वहां पहुंचने वाले व्यक्ति को ऊर्जा से परिपूर्ण कर देती है। हृदय कभी-कभी इस विचार से भारी हो जाता है कि इतना जीवन गुजर गया और हम अपनी इस विरासत यानी अपने तीर्थों की पावन मिट्टी स्पर्श नहीं कर पाए और इस कारण उन लोगों से स्वयं को कमतर करके देखने लगते हैं जो तीर्थों का दर्शन कर खुद को धन्य मानते हैं। एक ग्लानि जैसा भाव मन को घेर लेता है, लेकिन इस तथ्य से मन में ग्लानि का भाव महसूस करने की जरूरत नहीं है।

यदि हम अपनी जीवनचर्या के अतीत व वर्तमान पर ध्यान दें तो पाएंगे कि किन्हीं परिस्थितियों के कारण हम अपने जीवनकाल में भले ही अनेक पवित्र तीर्थ स्थलों का दर्शन न कर सके हों, लेकिन फिर भी हम अनेक कर्म करते रहते हैं जो किसी तीर्थ सरीखी शांति और पुण्य प्रदान कर पाने में समर्थ होते हैं। इस कथन का यह प्रयोजन नहीं है कि हम तीर्थों के महत्व को किसी भी रूप में नकार रहे हैं। अपनी जीवन यात्रा में अपनी सीमा से बाहर निकलकर, निःस्वार्थ भाव से दूसरों के प्रति कुछ कर जाने में तर जाने की अनुभूति किसी तीर्थ से कम तो नहीं। हम जाने-अनजाने अपने चारों ओर छोटे-छोटे तीर्थ बनाकर पुण्य कार्य करते हैं। किसी भूखे को भोजन, अभावग्रस्त की मदद, अनपढ़ को ज्ञान प्रदान कर शिखर तक पहुंचाने का जीवन पर्यंत प्रयास क्या तीर्थ-दर्शन से कम पावन व सुखवर्धक है? विविध कलाओं या खेल जैसी क्रीड़ाओं में पारंगत होना व उस ज्ञान को बांटना अपने में तीर्थ जैसी अनुभूति प्रदान करता है। आध्यात्मिक तीर्थस्थलों तक पहुंचना एक सौभाग्य है, परंतु यदि ऐसा न हो पाए तो अपनी रचनात्मक कार्यक्षमता व सकारात्मक सोच से अपने तीर्थ स्वयं ही बनाने का प्रयास करना चाहिए। लोगों के साथ परोपकार भाव अपनाकर आप पुण्य की प्राप्ति व मोक्ष के मार्ग को प्रशस्त करने में समर्थ हो सकते हैं। यह लक्ष्य कठिन तो है, लेकिन असंभव कदापि नहीं।

छाया श्रीवास्तव

पृथ्वी को बचाने की अनोखी कोशिश

मुकुल व्यास

वैज्ञानिक ज्वालामुखी विस्फोट की कृत्रिम प्रक्रिया अपनाकर पृथ्वी के तापमान को कम करने की कवायद में जुटे हैं

अमेरिका में हार्वर्ड विश्वविद्यालय की इंजीनियरिंग टीम ने एलान किया है कि वह एक बड़े ज्वालामुखी विस्फोट के प्रभावों को दोहरा कर सूरज की आंच को मंद करना चाहती है। वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि ऊपरी वायुमंडल में सूक्ष्म कणों के छिड़काव से सूरज की कुछ किरणें पृथ्वी पर आने से पहले ही वापस अंतरिक्ष की ओर परावर्तित हो जाएंगी। इससे ग्लोबल वार्मिंग को रोकने में मदद मिलेगी। जलवायु को कृत्रिम रूप से प्रभावित करने वाले प्रोजेक्ट 'जियो-इंजीनियरिंग' के अंतर्गत आते हैं। फिलीपींस में 1991 में माउंट पिनाटुबो ज्वालामुखी फटने के बाद दो करोड़ टन से अधिक सल्फर डायोऑक्साइड ऊपरी वायुमंडल (स्ट्रैटोस्फीयर) में फैल गई थी।

सूरज की किरणों को अवरुद्ध करने वाले बादलों ने 18 महीने तक पृथ्वी के तापमान को 0.5 डिग्री सेल्सियस कम बनाए रखा था। हार्वर्ड की टीम कुदरती तौर पर हुए इस प्रभाव को दोहराना चाहती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि यदि तापमान में ऐसी कटौती की अवधि को बढ़ा दिया जाए तो जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों को रोका जा सकता है। हार्वर्ड के जियो-इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट का नाम स्कोपेक्स (स्ट्रैटोस्फेरिक कंट्रोल्ड परटरबेशन एक्सपरिमेंट) है। इस पर करीब 30 लाख डॉलर खर्च आएगा।

इस प्रयोग के तहत अमेरिका के दक्षिण-पश्चिम में एक एयरशिप को करीब 20 किलोमीटर की ऊंचाई पर भेजा जाएगा। एयरशिप आकाश में चाक डस्ट (कैल्शियम कार्बोनेट) का धुआं छोड़ेगा। इस रसायन के छिड़काव के बाद यह देखा जाएगा कि इससे सूरज की रोशनी कितनी बिखरी और ऊपरी वायुमंडल में क्या-क्या रासायनिक परिवर्तन हुए। वहीं ब्रिटिश वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि ऐसे प्रयोगों से वर्षा चक्र अस्त व्यस्त हो जाएगा जिससे दुनिया के बड़े हिस्सों में अकाल और सूखा पड़ेगा।पृथ्वी को सूरज से दूर करने के सुझाव पर नासा के वैज्ञानिकों ने गंभीरता से विचार किया था। इससे भी ज्यादा अजीबोगरीब सुझाव यह है कि पृथ्वी को अपनी जगह से खिसकाने के लिए धूमकेतुओं को पृथ्वी की दिशा में मोड़ दो।

अमेरिका की येल यूनिवर्सिटी में खगोल विज्ञान के प्रोफेसर ग्रेग लाफलिन ने कहा कि वैज्ञानिक किसी धूमकेतु या क्षुद्रगह को सावधानीपूर्वक पृथ्वी की तरफ इस तरह मोड़ सकते हैं कि वह हमारे बगल से निकल जाए और अपने गुरुत्वाकर्षण खिंचाव से पृथ्वी को सौरमंडल में दूर ले जाए। उनका कहना है कि यह कोई अनोखी तकनीक नहीं है। पृथ्वी की तरफ आने वाले क्षुद्रग्रहों और धूमकेतुओं की दिशा मोड़ने के लिए ऐसी ही तकनीक अपनाने का सुझाव दिया गया है। उन्होंने कहा कि हमें पृथ्वी को आगे खिसकाने के लिए कोई बड़ी ताकत नहीं चाहिए, सिर्फ उचित योजना बनानी पड़ेगी। इस सुझाव के समर्थकों का कहना है कि इससे हमारे ग्रह के जीवन में छह अरब वर्ष का इजाफा हो जाएगा। लेकिन इस सुझाव के आलोचकों ने कहा कि गणना में छोटी सी भूल से विनाशकारी टक्कर हो सकती है जो कुछ जीवाणुओं को छोड़कर समस्त जीवों का सफाया कर देगी।

(लेखक स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं)

राजरंग

अटक गई सांस

हाल ही में चुनावी गठजोड़ कर उत्तर प्रदेश की राजनीति में छोटे यादव ने भले ही अपनी राजनीतिक चतुराई का डंका पीट दिया हो, लेकिन उनकी पार्टी के बड़े-बड़े नेताओं के होश फाख्ता हो गए हैं। कल तक खुशी से मिठाई बांटने वाले इन नेताओं तक को मालूम नहीं कि आगामी चुनावों में उनका अपना टिकट पक्का होगा अथवा नहीं। समझौते में अभी यह तय नहीं हो पा रहा है कि कौन सी सीट गठबंधन के किस घटक दल के खाते में जाएगी। खुद पर खतरा मंडराने का आभास होते ही उनकी मुश्किलें बढ़ गई हैं। इन दिनों ऐसे नेताओं की पूरी कोशिश पिछले लोकसभा व विधानसभा चुनावों में अपनी सीट पर मिले मतों की छानबीन करने की है। पार्टी में उच्च पदस्थ नेताओं को भी इस बारे में कुछ नहीं पता है। ऐसे में यह कठिनाई और बढ़ गई है। दरअसल, छोटे यादव पार्टी में किसी और की सुनने को तैयार नहीं हैं।

अभिभूत हैं बड़े साहब

बजट के बाद वैसे तो सरकार के सभी मंत्री और राजग सांसदों के चेहरे खिले हुए और हौसले बुलंद है, लेकिन सरकार के एक वरिष्ठ मंत्री उसके पहले से ही बड़े अभिभूत नजर आ रहे है। हालांकि इसकी वजह किसी की भी समझ से परे है। असल में हुआ यूं कि उन्हें अब रामराज्य से कम कुछ दिख ही नहीं रहा है। राष्ट्रपति के अभिभाषण की तुलना भी उन्होंने भगवद्गीता से कर दी। उन्होंने अंतरिम बजट को भी रामराज्य की तरफ बढ़ने वाला कदम बताया। इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात जो है, वह यह कि पिछले दिनों वह पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के एक कार्यक्रम में पहुंचे और बोलने के लिए खड़े हुए तो उन्हें पृथ्वी विज्ञान बोलने में बार-बार परेशानी हुई, इसके बाद तो उन्होंने मंत्रालय का नाम ही बदलने की सलाह दे डाली। बोले, विभाग का नाम भारतमाता मंत्रालय क्यों नहीं रख दिया जाए। हालांकि इसके बाद जमकर ठहाके भी लगे। खैर जो भी हो, पर मंत्री जी के अचानक इस बढ़े हुए आत्मविश्वास से सभी अचंभित जरूर हैं।

उड़ी का जोश

लालकृष्ण आडवाणी संभवतः उन गिने चुने राजनेताओं में से एक हैं जिनका फिल्मों के प्रति जबरदस्त आकर्षण जगजाहिर है। वह खुद बताते हैं कि शुरुआती संघर्ष के दिनों में हिंदी फिल्में ही उनके और उनके साथी स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के लिए गम भुलाने का जरिया बनती थीं। इस उम्र में भी फिल्म देखने का उनका शौक उसी तरह से जवां है। अंतरिम बजट के दिन भी इसकी बानगी तब दिखाई दी जब आडवाणी ने धीरे से वित्त मंत्री गोयल को उड़ी के बारे में बोलने के लिए उकसाया। लोकसभा के इस पूरे कार्यकाल में आडवाणी अमूमन चुप्पी ही साधे रहे हैं, लेकिन शुक्रवार को बजट के दिए उन्होंने गोयल को उड़ी की याद दिलाई और गोयल ने भी इसका पालन किया। आडवाणी ने सिर्फ उड़ी के जिक्र के दौरान मेज बहुत जोश से थपथपाई, वरना बजट भाषण के अधिकांश समय वह चुपचाप ही बैठे रहे।

ढीले हुए तेवर

भाजपा के उन सांसदों के तेवर फिर ढीले पड़ने लगे हैं जिनके टिकट आगामी लोकसभा चुनाव में कटने की आशंका है। सरकार की बजट घोषणाओं के बाद ऐसे सांसदों की अकड़ ढीली पड़ने लगी है जो बीते दिनों तीन राज्यों के विधानसभा चुनाव में पार्टी के हारने के बाद यह कहते घूमते दिख रहे थे कि पार्टी अब कैसे उनके टिकट काटेगी। दरअसल राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा आम थी कि लोकसभा चुनावों में मौजूदा सांसदों खासतौर पर उत्तर प्रदेश के कई मौजूदा सांसदों की जगह पार्टी नए चेहरों को प्राथमिकता देगी। जिन सांसदों को खुद इस बात का अहसास था वे किसी तरह अपनी स्थिति को ठीक करने में जुटे थे। लेकिन मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में सरकार से बाहर होने के बाद इन सांसदों ने राहत की सांस ली थी। लेकिन शुक्रवार को अंतरिम बजट पेश होने के बाद ही इनके चेहरे का रंग उड़ गया। ऐसे कई सांसद तो संसद के गलियारे में यह कहते हुए भी सुनाई दिए कि अब टिकट पाने की जुगत भिड़ाने में फिर से जुटना होगा।

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त. पूर्व प्रधान संपादक-स्व.नरेन्द्र मोहन. संपादकीय निदेशक-महेन्द्र मोहन गुप्त. प्रधान संपादक-संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए: नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग,रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्करण) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 23359961-62, नोएडा कार्यालय : 0120-3915800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721 *इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं न हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई शुल्क अतिरिक्त।